years 1987 and 1988 and again on 6th August 1990. But this proposal did not figure among those recommended by the committee.

(c) and (d) Do not arise.

Recommendations of Prashar Committee

4207. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the decisions taken by Government on the twenty first recommendations of the Parashar Committee appointed in July, 1987?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): The 21 recommendations made by the Parashar Committee covered inter alia various subjects like review of the concept of district pattern of sorting, strengthening mail monitoring work, evolving systematic and periodical review and revision of mail arrangements and re-introductions of sorting in running sections. While the recommendations made by the Parashar Committee in respect of most of the items have been taken into account in streamlining various instructions, no final decision has yet been taken on the question of restoration of sorting in running sections.

Provision of Telephone Connections

4208. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1195 given in the Rajya Sabha on 1st December, 1992 and state:

(a) whether his attention has been drawn to recent reports that the Department of Telecommunications has drawn up a plan to provide telephone connections within six months to the registrants under OYT category in major exchanges all over the country by March, 1993;

(b) what is the anticipated number of registrants waiting for the grant of telephone connections by the end of March, 1993 both to OYT and General Category; and

(c) the steps Government propose to take to clear this number within the short period of time?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No such Plan has been drawn Sir. However effort are being made to clear the OYT waiting list of more than a months old at the earliest.

(b) The waiting list under various categories as on 31-10-92 is

OYT	2.00 lakhs
Non-OYT	26.53 lakhs

Waiting list projection as on 31-3-93 based on past trend is likely to be around 30 lakhs. However actual break-up between OYT and Non-OTY waiting list depends on the preference of the subscribers while registering for new connections.

(c) 8th five year Plan envisages to provide 75 lakh new Telephone connections during the plan period to meet the demand. The objectives in this regard are:

Telephone connection practically on demand in the rural/Tribal areas, and small and medium towns.

Connection within two years of the registration of telephone in the large cities by the end of the 8th plan period subject to the availability of the resources.

Expansion programmes for major exchange system is being drawn accordingly and supply of required equipment and cable is being arranged.

हरियाणा में विभागेत्तर कर्मचारी

4209. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक विभाग विभागेत्तर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति के

का सही ढंग से आंकलन कर उनके पारिश्रमिक में वृधि करने और नियमित कमचारियों की तरह उनकी सेवाएं स्थाई करने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में ऐसे कर्मचारियों की जिलावार संख्या कितनी है जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं परन्तु जिनकी सेवाओं को स्थाई नहीं किया जा सका है जिसके परिणामस्वरुप उन्हें अपने परिवारों के भरण-पोषण में वित्तीय कठिनाइयां पेश आ रही हैं और इन सभी कर्मचारियों की सेवाओं को जो दिहाड़ी/मस्टर रोल पर दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, कब तक स्थाई कर दिया जाएगा; और

(ग) इस संबध में सरकार के सामने आने वाली मुख्य कठिनाइयां क्या क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० एंगैया नायडू) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) हरियाणा डाक सर्किल मे तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अतिरिक्तों विभागीय एजेंटो की जिला वार कुल संख्या निम्नानुसार है :—

जिला	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या
करनाल	227
पानीपत	204
जींद	257
भिवानी	365
गुडगांव	280
महेन्द्रगढ़	212
रेवाड़ी	228
कुरुक्षेत्र	204
कैथल	190
रोहतक	404
सोनीपत	289
फरीदाबाद	200
अम्बाला	352
यमुनानगर	204
हिसार	404
सिरसा	353

अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के अंशकालिक एजेंट हैं जिनसे एक दिन में 2 से लेकर 5 घंटे तक काम लिया जाता है । उन्हें मासिक समेकित भत्ता दिया जाता है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य घंटों पर आधारित होता है । वे अपनी वरिष्ठता के कारण विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारियों के बतौर नियुक्त होने के भी पात्र होते हैं । वे पोस्टमैन के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भी बठ सकते हैं । कुछ शर्तें पूरी करने पर उन्हें डाक सहायक के बतौर लेने के बारे में भी हाल ही में निर्णय लिया गया है । उन्हें उसी दर से और उतने ही समयान्तराल पर बोनस और मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है जिस प्रकार कि यह विभागीय कर्मचारियों को मिलता है । नौकरी से रिटायर होने पर उन्हें एक फार्मूले पर आधारित ग्रेच्युटी भी दी जाती है । वे साइकिल, स्टेशनरी और कार्यालय भत्ता आदि जैसे कुछ भत्ते पाने के भी पात्र हैं । चूंकि, ये एजेंट सीमित घंटों के लिए अंशकालिक आधार पर कार्य करते है तथा साधारण किस्म का डाक संबंधी काम करते हैं, इसलिए उन्हें नियमित कर्मचारियों का दर्जा देना या उन्हें नियमित कर्मचारी मानने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cases before Settlement Commission

@4210. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of cases pending for disposal by the Settlement Commission (Income-tax/Wealth-tax) for 1990-91 and 1991-92;

(b) the number of cases actually disposed of by it; and

@Previously Unstarred Question 3278, transferred from 17th December, 1992.